

पांच दशक का वनवास खत्म, हनुमाननगर-चंद्रनगर के सूयो परियोजना विस्थापितों को मिला जमीन का मालिकाना हक

पालघर(उत्तरशक्ति) में सूर्या
परियोजना के लिए धर्मजी बांध के
निर्माण के तहत विस्थापित होकर
पालघर तहसील के हनुमाननगर
और चंद्रनगर में बसाये गये परिवारों
का पांच दशक लंबा संघर्ष
असिधकार समाप्त हो गया है। इन
परिवारों को उनकी जमीन का
मालिकाना हक प्रदान करने संबंधी
शासन निर्णय की प्रति मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार 9
अक्टूबर को ग्रामीणों को सौंपी। राज्य
सरकार के हासेवा संकल्प
अभियान-2026हक के अंतर्गत
हनुमाननगर में आयोजित कार्यक्रम
में मुख्यमंत्री ने इसे दोनों गांवों के
लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा
कि अब इन परिवारों के लिए न्याय
और विकास की नई सुबह शुरू हुई
है। मुख्यमंत्री ने संबंधित
अधिकारियों को निर्देश दिया कि
अगले तीन महीने के भीतर
हनुमाननगर और चंद्रनगर के प्रत्येक
पात्र लाभार्थी को सातबारा (भूमि
स्वामित्व अभिलेख) उपलब्ध

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दस्तावेजों में तकनीकी त्रुटियों के कारण कोई भी पात्र परिवार अपने अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। धामणी बांध परियोजना के कारण विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया वर्ष 1968 में शुरू हुई थी। वर्ष 1978 तक इन परिवारों को हनुमाननगर और चंद्रनगर में बसाया गया तथा वर्ष 1982 में पुनर्वास पूरा होने की घोषणा की गई। हालांकि, जमीन की माप, सीमांकन और राजस्व अभिलेखों से संबंधित प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण ग्रामीण दशकों तक अपनी ही जमीन के कानूनी मालिकाना हक से वंचित रहे। ग्रामीणों के लगातार प्रयासों, पालघर जिले के पालकमंत्री एवं वनमंत्री गणेश नाईक, जिलाधिकारी डॉ. इंद्र प्रभावी तथा परिवार योजना प्राविताओं की समिति के सहयोग से यह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक

पहुँचा। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को 15 दिनों के भीतर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इस निर्णय से पांच दशक से लंबित समस्या के समाधान का रास्ता साफ हो गया।

मुख्यमन्त्र दैवद्र फडवावस
ने कहा कि शासक का निर्णय रहना
कागजों तक सीमित नहीं होना
चाहिए, बल्कि इसका लाभ प्रत्येक
पात्र परिवार तक पहुंचना चाहिए।
उन्होंने कोंकण विभागीय अयुक्त
और जिलाधिकारी को समझाया
तीरके से सातवारा अभिलेख जारी
करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों को
मांग पर मुख्यमंत्री ने हनुमाननगर
और चंद्रनगर को अपनी ओर से
जिलाधिकारी को गोरे देते की घोषणा
भी की। उन्होंने दोनो गांवों में
बुनियादी सुविधाओं का
पुनर्मूल्यांकन कर सड़क, पेयजल



और अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित ग्रामीण विकास से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने आवासन दिया कि विकास कार्यों के लिए धन और निणयों की कमी नहीं होने दी जायेगी। तीन महीने बाद वे स्वयं इन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। चन्द्रनगर में स्वतंत्र ग्राम पंचायत स्थापित करने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार के विचाराधीन है। जनगणना प्रक्रिया के

चलते नई ग्राम पंचायतों के गठन पर फिलहाल प्रतिबंध होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्ताव पूरा होने पर जनगणना आयुक्त से विशेष अनुमति लेकर चंद्रनगर ग्राम पंचायत को शीघ्र मंजूरी देने का प्रयास किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जमीन के मालिकाना हक का यह निर्णय केवल हनुमाननगर और चंद्रनगर तक सीमित नहीं रहेगा। पालघर जिले में विभिन्न विकास

परियोजनाओं के कारण पुनर्वसितता
हूए, लेकिन अब तक जमीन
अधिकार नहीं वने वाले सभी पात्र
परियोजना प्रभावितों को इसी तर्ज पर
न्याय दिलाया जायेगा। उन्होंने कहा
कि वन अधिकार पट्टों के वितरण में
पालघर जिला राज्य में अग्रणी है
अंतिम पात्र लाभार्थी को वन
अधिकार पट्टा मिलने तक यहां
प्रक्रिया जारी रहेगी। साथ ही वन
अधिकार धारकों तक शासन की

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा।

पालघर जिले के विकासमंत्री ने रोडघर प्रस्तुत करते हुए भूमिपुत्रों ने कहा कि वाद्यध्वज बंदरागाह, प्रस्तावित विमानतल, बुलेट ट्रेन और विभिन्न सड़क परियोजनाओं के कारण पालघर महाराष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार बना रहा है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं में स्थानीयवासियों लोगों और भूमिपुत्रों के हित सर्वोपरि रखा जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए परियोजनाओं से अधिकक महत्वपूर्ण लोग हैं। भूमिपुत्रों को भूमिहीन करने वाला विकास, विकास नहीं बल्कि विनाश होगा। उन्होंने बताया कि पुनर्वास के लिए हम मानक निर्धारित किए जा रहे हैं। इनके तहत बेहतर बुनियादी सुविधाएं, सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं और रोजगार के अवसर

पुनर्वास का अभिन्न हिस्सा होगा विकास का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचे और उनसे परिवारों को आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसी दृष्टिकोण से परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने रॉड मोदी के जन्मदिन और ह्रासर्वजन हितायुद्ध के विचारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय, किसान, खेत मजदूर और महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सहभागी बनानाकर पालघर जिले को महाराष्ट्र के पांच सबसे विकसित जिलों में शामिल करना उनका लक्ष्य है। ग्रामीणों को भावुक संदेश देने हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्रीराम और पांडवों के वनवास से भी अधिक लंबा संघर्ष आपने किया है। आज आपका वनवास समाप्त हुआ है और आपके जीवन में नई सुबह शुरू हुई है। उन्होंने इस निर्णय में योगदान देने वाले अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्थाओं और नागरिकों को अभिनंदन किया।

पैडल-पैडल में गुंजेगा नशामुक्त भारत का संकल्प

वाराणसी। गंगा का लहरा के
सानिधिक में रविवार की सुबह
सांक्रिल के पहिये फिटनेस का
पैराम लूकेर अगे बढ़े। पैडल के
साथ गुंजेना नशामुत भारत का
संस्कृत और युवाओं को मिलेगा
स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का
संदेश। मौका होगा फिट इंडिया सडे
ऑन सांक्रिल के १५वें संस्करण
का, जिसमें केन्द्रीय युवा कार्यक्रम
एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री
डॉ. मनसुख मांडविया युवाओं के
साथ सांक्रिल चलाकर अभियान
का नेतृत्व करेंगे।

नमी घाट पर राविवर सुबह छह बजे शुरू होने वाले इस आयोजन की थीम फिटनेस भारत के लिए नशामुक्त युवा है। यहां से साइकिल यात्रा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक जाएगी। आयोजन में युवा, फिटनेस प्रेमी, आम नागरिक और खेल जगत के हस्तियां शामिल होंगे। उद्देश्य साफ है—युवाओं को नशे से दूर



खरकर खेल, व्यायाम और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना।
आयोजन में 2026 के आद्यचीनागोया एशियाई खेलों के पदक विजेता खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। इनमें महिलाओं की 400 मीटर दौड़ की कांस्य पदक विजेता प्राची चौधरी, महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज और 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली परल चौधरी, रिले स्पर्धाओं में पदक हासिल करने वाले जय कुमार और भारतीय हॉकी टीम के स्वर्ण पदक

विजयें राज कुमार पाल
शामिल हैं। इन खिलाड़ियों
की भागीदारी युवाओं की
अनुशासन, नियमित
अभ्यास और हृदय संकल्प
की प्रेरणा देगी। खेल के
मैदान में देश का गौरव
बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के
साथ साइकिल चलाना
प्रतिभागियों के लिए
फिटनेस को जीवन का
हिस्सा बनाने का संदेश भी होगा।

याग-जुवा स बढ़ाया उस्ताहः
साइकिल यात्रा के साथ नमो घाट पर
योग सत्र, जुवा, मनोरंजक खेल और
संवादात्मक गतिविधियां भी
आयोजित होंगी। इनके जरिये लोगों
को नियमित व्यायाम और सक्रिय
जीवनशैली के लिए प्रोत्साहित किया
जाएगा। अभियान इस विचार को
मजबूत करता है कि फिट रहना
बिस्की एक दिन की कवायद नहीं,
बल्कि रोजमर्रा की आदत होनी
चाहिए.

♦ कलश स्थापना के साथ आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ, नौ दिनों तक गूंजगा मां दुर्गा का जयकारा

♦ 512 सावजनिक पूजा
पंडालों में सजेगी देवी
प्रतिमा, देश के प्रसिद्ध
मंदिरों और समसामयिक
विषयों की झलक बनेंगे
आकर्षण
सुरेश गांधी

दस्तक के साथ ही काशी की गलियों में भक्ति का रंग गहराने लगा है। कहीं मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं बांस, कपड़े और आकर्षक सज्जा से घरे पूजा पंडाल आकार ले रहे हैं। धर्म पूजन सामग्री जुटाई जा रही है और बाजारों में चुनरी, नारियल, कलश,

दीपक, फूल-माला तथा देवी के शृंगार की वस्तुओं की खरीदारी तेज हो गई है। रविवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही काशी नी दिनों तक शक्ति की आराधना में बहू जाएगी। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा पर शुरू होने वाला यह पर्व केवल पूजा-पाठ का अनुष्ठान नहीं, बल्कि शक्ति, सन्धान और सामाजिक उल्लास का उत्सव भी है। घरों में कलश स्थापना और देवी के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना होगी। मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजही बढ़ेगी तो शाम ढलते ही पूजा पंडालों में सजी रोशनी, देवी प्रतिमाओं और कलात्मक सज्जा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगेगी।

शुभ मुहूर्त: शारदीय नवरात्र का आरंभ आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर होगा। पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर की रात 9:19 बजे शुरू होकर 11



अक्टूबर की रात लगभग 9:30 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के आधारारारा रात पर रविवार को नवरात्र का पहला दिन माना जाएगा। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त को लेकर अलग-अलग पंचांगों में कुछ अंतर है। सामान्यतः पंचांग गणना के अनुसार सुबह 6:19 से 10:12 बजे तक घट स्थापना का समय दिया गया है वहीं, बीएचयू के ज्योतिषार्चार्यों प्रो. विनय पांडेय के हवाले से प्रकाशित किनारी की स्थानीय गणना में सुबह

11:20 से दोपहर 12:07 बजे तक 47 मिनट का अभिजित मुहूर्त बताया गया है। इस वर्ष चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग का संयोग होने के कारण मुहूर्त के चयन में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

स्थापना: घट स्थापना के लिए पूजा स्थल की सफाई करके उसे गंगाजल अथवा स्वच्छ जल से पवित्र करें लकड़ी की चौकी या उपयुक्त स्थान पर लाल अथवा पीला वस्त्र बिछाएं

उसके पास मिट्टी के पात्र में स्वच्छ मिट्टी भरकर जौ बोएं। जौ को समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद तांबे, पीतल अथवा मिट्टी के स्वच्छ कलश में जल भरें। परंपरा के अनुसार उसमें अक्षत, सुपारी, सिक्का और सुगंधित द्रव्य रखे जा सकते हैं।

कला का मुख पर आम अथवा उपलब्ध थीं परते रखें और ऊपर नरियल पत्रिका करें। कला पर रोली से स्वस्तिक बनाएं तथा मौली बांधें। अरु मां दुर्गा की प्रथमा चंद्रा के सामने दीपक जलाकर गणेश वंदना करें। इसके बाद मां शैलपुत्री का स्मरण करते हुए कलश स्थापना का संकल्प लें। घट स्थापना के समय यह मंत्र पढ़ सकते हैं— ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चागुण्डव्यो विच्ये। यह देवी उपासना का प्रसिद्ध मंत्र है। कलश स्थापना के पारंपरिक वैदिक मंत्र और संकल्प अपने पुरोहित से भी पढ़वाए जा सकते हैं।

प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से भड़कीं प्रियंका गांधी, बोलीं-लोकतंत्र नहीं, देश में चल रही तानाशाही

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर शनिवार को आरोप लगाया कि "भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहा, बल्कि प्रभामंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तानाशाही चलाई जा रही है।" प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा कि लोकतंत्र को समजोर करने और उसे नष्ट करने में सहयोग करने वाले लोग देश के खिलाफ देशद्रोह कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट करके सांसद लगाया कि पहले 254 सांसदों के साथ मारपीट की गई और उन्हें पूरी तरह अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया, जिससे उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया



गया। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी की घेराबंदी कर दी गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली को चारों ओर से बैरिकेडिंग करके सील कर दिया गया, ट्रेनों और मेट्रो सेवाओं को रोकना गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया और जगह-जगह चेक पोस्ट बना दिए गए। प्रियंका गांधी के मुताबिक, अपने संवैधानिक अधिकार के तहत विरोध-विरोधियों के साथ मारपीट की गई और उन्हें हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए।

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर
भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत
ने शनिवार को कहा कि कानून का
उल्लंघन करने वाले बच्चों के नाम
समाचारों एवं इंटरनेट पर सार्वजनिक
नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि यह
व्यावस्था उसकी परिस्थिति को
दशांता है, न कि उसकी पहचान को।
प्रधान न्यायाधीश ने उच्चतम
न्यायालय की किशोर न्याय समिति

द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के सहयोग से आयोजित किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के 10 वर्ष: प्रगति, चुनौतियाँ और अगले दशक की प्रार्थनिकाएँ विषय पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद कहा कि किसी कानून के लिए 10 वर्ष का समय कम होता है लेकिन

यह किसी बच्चे के बचपन के आधे से भी अधिक समय के बराबर है। उन्होंने कहा कि 2015 का यह अधिनियम इस सोच पर आधारित है कि किसी बच्चे पर अपराधी ठहरा दिया जाए तो उसे दूसरा मौका दिया जाए तो उसके समाज का एक उपयोगी सदस्य बनने की संभावना वहीं अधिक होती है। उन्होंने कहा, यह यात्रा वास्तव में

तभी पूरी होती है, जब अतीत की छाया भविष्य पर पड़नी बंद हो जाए। इसके लिए हमें पुराने रिकॉर्ड समय पर गूट करने होंगे और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के नाम समाचारों और इंटरनेट पर सार्वजनिक होने से रोकने होंगे, क्योंकि एक बार इंटरनेट पर आने के बाद ये नाम वषों तक वहां बने रह सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जनवरी 2016 में जब यह अधिनियम लागू हुआ था, तब किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किए गए 15 वर्षीय बच्चे की उम्र आज लगभग 25 वर्ष होगी और इस अधिनियम ने उस बच्चे से जो पहला वादा किया था, वह इसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों में ही निहित है। उन्होंने कहा, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे वास्तव में बच्चे की परिस्थिति को दशाता हैं, न कि उसकी पहचान को। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे बच्चों की परिस्थितियां आमतौर पर कठिन होती हैं।



उन्होंने कहा कि उनकी कष्टानियों में अक्सर पढ़ाई बीच में छूटती है, परिवारों के मुश्किल हालात से गुजरने और गरीबी की समस्याएँ सामने आती हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी बच्चे से बातचीत करने और उसकी ओर से बोलने वाला कोई नहीं है, तो उसे अपनी बात रखने का अधिकार देने का कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि इसी कारण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की 2024 का बाल-अनुकूल विधिक सेवा योजना में पुलिस थानों में बच्चों के लिए पब्लिक और प्रत्येक किशोर न्याय

बोर्ड में विधिक सेवा क्लिनिक की व्यवस्था की गई है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा,
इसके बावजूद कई बोर्ड में
अब भी ऐसे क्लिनिक नहीं हैं।
इनके अभाव में बच्चे की
देखभाल और कल्याण से जुड़े
सुरक्षाती फैसले उचित
कानूनी प्रतिनिधित्व के बिना
लिए जाने की संभावना है।
उन्होंने विधिक सेवा संस्थानों से
बच्चों के लिए प्रशिक्षित न्याय पक्ष
के वकीलों का एक अलग प्रकोष्ठ
बनाने पर भी विचार करने का आग्रह
किया, ताकि प्रत्येक बच्चे को
शुरूआत से ही एक समर्पित वकील
मिल सके। प्रधान न्यायाधीश ने
नियमित और स्वतंत्र मूल्यांकन की
आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि
निजता का उचित ध्यान रखते हुए
यह पता लगाया जा सके कि कितने
बच्चे दोषारोपित विद्यार्थ्य गए, कितनों
को रोजगार मिल और कितनों को
फिर कई किशोर न्याय बोर्ड के
समक्ष पेश नहीं होना पड़ा।

TIWARI'S SARASWATI CLASSES

— Since 1992 —

Parents' First Choice for **34+ Years**

Prof. Dr. Dayanand Tiwari
Founder & Academic Director

ADMISSIONS OPEN

9th | 10th | 11th | 12th SCIENCE

NEET | JEE | MHT-CET

10 DAYS FREE DEMO

Attend Classes • Experience Our Teaching
Take Admission After Satisfaction
(No Hidden Conditions)

- ✓ 34+ Years of Academic Excellence
- ✓ Experienced & Dedicated Faculty
- ✓ Personal Attention
- ✓ Printed Notes & Regular Tests
- ✓ Strong Foundation for Boards & Competitive Exams

📍 Santacruz Branch
101 Sai Chambers,
Opp. Santacruz Railway Station (East),
Near Depot, Santacruz (E), Mumbai-400055

📍 Sion Branch
Opp. SIES College (Old),
Near Gurukripa Hotel,
Sion (West), Mumbai

— Limited Seats / Small Batch Size —

CALL NOW:

7738007373



DAKS REHAB CENTRE
(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)

DAKS REHAB CENTRE

(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)

Contact us: 9820519851

विल्डिंग नंबर 3, प्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीबी नगर मुंबई-37

*** Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre**

- * बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
- * वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
- * **DM/HT/THYROID** इन सब से कैसे बचें
- * **NGO** में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
- * चिकिस्ता उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
- * एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
- * पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
- * मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
- * विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
- * मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तियों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकिस्ता सुविधा उपलब्ध







Multi Solutions

WHAT WE DO ?

COMPUTER & CCTV

- Laptop, Desktop, CCTV, Sales Service & Rental
- Networking
- Software Installation
- Data Recovery
- Antivirus

SMART AUTOMATION

- Automation
- Biometric
- Smart Home App Control
- All Type of Electric Work





Shop No13, First Floor, Zahoor Nagar, Mustafa Market, Near Rehmani Hotel, Kherani Road, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai - 400072.

Mithun Prajapati
 +91 9220 555 717

नित्य घटित हो रही घटनाएँ, शासन देखे, चुप रह जाए?



-विक्रम दयाल

आज के बदलते सामाजिक परिवेश में एक प्रश्न बार-बार जनमानस को झकझोरता है कि जब समाज में नित्य नई-नई घटनाएँ घटित हो रही हैं, जब अपराध, शोषण, असुरक्षा, भ्रष्टाचार और मानवीय संवेदनहीनता की खबरें लोगों को विचलित कर रही हों, तब शासन-प्रशासन की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या घटनाओं को देखना, उन पर औपचारिक प्रतिक्रिया देना और फिर अगली घटना की प्रतीक्षा करना ही व्यवस्था की जिम्मेदारी है? अथवा शासन का वास्तविक दायित्व समस्याओं की जड़ तक पहुँचकर उनका स्थायी समाधान करना भी है? लोकतंत्र में शासन केवल सत्ता संचालन का माध्यम नहीं, बल्कि जनविश्वास, जनसुरक्षा और जनकल्याण का उत्तरदायी आधार है। जनता अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है कि वे उसकी समस्याओं को समझें, उसकी अपाज सुनें और उसे भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। जब आम नागरिक अपने अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने लगे, तब व्यवस्था के सामने आत्ममंथन का प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है। घटनाएँ अनेक, समाधान कहीं? समाज में घटित होने वाली प्रत्येक घटना के पीछे अलग-अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं। कहीं व्यक्तिगत वैमनस्य होता है, कहीं आर्थिक विवशता, कहीं सामाजिक भेदभाव, तो कहीं कानून का भय कम होने के कारण। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, कमजोर वर्गों का शोषण, टगी, हिंसा, बेरोजगारी से उपजी निराशा और सार्वजनिक जीवन में बढ़ती असहिष्णुता जैसी समस्याएँ केवल समाजचारों का विषय नहीं हैं। इनके पीछे किसी परिवार का दर्द, किसी माँ की चिंता, किसी पिता की विवशता और किसी बच्चे के भविष्य का संकट छिपा हो सकता है। प्रश्न यह नहीं कि हर घटना के लिए सीधे शासन को दोषी ठहरा दिया जाए। प्रश्न यह है कि ऐसी घटनाओं को रोकने, अपराधियों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए व्यवस्था कितनी तत्पर है। किसी घटना के बाद जाँच का आश्वासन देना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है जाँच का निष्पक्ष निष्कर्ष, समय पर न्याय और ऐसी व्यवस्था, जिससे उसी घटनाओं को रोकने, अपराधियों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए व्यवस्था कितनी तत्पर है। किसी घटना के बाद जाँच का आश्वासन देना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है जाँच का निष्पक्ष निष्कर्ष, समय पर न्याय और ऐसी व्यवस्था, जिससे उसी घटनाओं को रोकने, अपराधियों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए व्यवस्था कितनी तत्पर है। किसी घटना के बाद जाँच का आश्वासन देना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है जाँच का निष्पक्ष निष्कर्ष, समय पर न्याय और ऐसी व्यवस्था, जिससे उसी घटनाओं को रोकने, अपराधियों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए व्यवस्था कितनी तत्पर है। किसी घटना के बाद जाँच का आश्वासन देना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है जाँच का निष्पक्ष निष्कर्ष, समय पर न्याय और ऐसी व्यवस्था, जिससे उसी घटनाओं को रोकने, अपराधियों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए व्यवस्था कितनी तत्पर है।

महिला सुरक्षा केवल नारा नहीं, जिम्मेदारी है:

किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहाँ महिलाओं को कितना सम्मान और सुरक्षा प्राप्त है। बेटियों को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समान अवसर देने की बातें तभी सार्थक होंगी, जब वे घर से बाहर निकलते समय भय और असुरक्षा से मुक्त महसूस करें।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध होने पर केवल कठोर कानूनों की चर्चा पर्याप्त नहीं है। शिकायत दर्ज कराने की सहज व्यवस्था, पुलिस की संवेदनशीलता, समयबद्ध जाँच, पीड़ित की पहचान और गरिमा की रक्षा तथा न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब को कम करना भी उनका ही आवश्यक है। साथ ही, परिवारों, शिक्षण संस्थाओं और समाज को ऐसी मानसिकता विकसित करनी होगी, जिसमें महिलाओं के प्रति सम्मान बचपन से ही संस्कार का हिस्सा बने।

सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल महिलाओं पर सावधानी बरतने का बोझ डालकर पूरी नहीं हो सकती। जिम्मेदारी उस व्यवस्था की भी है, जो कानून लागू करती है, सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाती है और अपराध करने वालों को जवाबदेह ठहराती है। महँगाई और बेरोजगारी भी सामाजिक चिंता हैं। समाज में अशान्ति और निराशा के अनेक कारण होते हैं। महँगाई से जूझता परिवार जब रसोई का खर्च पूरा करने में कठिनाई महसूस करता है, तब उसकी आर्थिक परेशानी धीरे-धीरे मानसिक तनाव में भी बदल सकती है। बेरोजगार युवा जब योग्यता और परिश्रम के बावजूद अवसरों के लिए संघर्ष करता है, तब उसके मन में भविष्य को लेकर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। यह कहना उचित नहीं होगा कि हर अपराध या सामाजिक समस्या का कारण केवल महँगाई और बेरोजगारी है। फिर भी इन चुनौतियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। रोजगार के अवसरों का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, छोटे व्यापारियों को सहाय्य और ज़रूरतपूर परिवारों को शोषण के जोर का वास्तविक लाभ पहुँचाना सामाजिक स्थिरता को मजबूत कर सकता है। सरकारी योजनाओं की घोषणा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी सफलता का वास्तविक पैमाना यह है कि उनका लाभ कितने जरूरतमंद लोगों तक पहुँचा। कागज़ों पर उपलब्ध सुविधा और नागरिक के जीवन में उपलब्ध सुविधा के बीच यह बड़ी दूरी बनी रह, तो उस दूरी को पाटना शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। शासन की चुप्पी से अधिक खतरनाक है जवाबदेही का अभाव: लोकतंत्र में प्रत्येक घटना पर शासन की प्रतिक्रिया का स्वरूप अलग हो सकता है। कभी तत्काल कार्रवाई आवश्यक होती है, तो कभी रथ्यों को पुष्टि के बाद निर्णय लेना उचित होता है। इसलिए हर मौन को दोष स्वीकार करना या हर प्रतिक्रिया को समाधान मान लेना भी सही नहीं है। किंतु किसी गंभीर समस्या पर लगातार निष्क्रियता, अस्पष्टता अथवा जवाबदेही के अभाव का अनुभव जनता के विश्वास को कमजोर कर सकता है। शासन की विश्वसनीयता केवल भाषणों और घोषणाओं से नहीं बनती। वह तब बनती है, जब कानून सचके लिए समान रूप से लागू हो, शिकायतकर्ता को सुना जाए, भ्रष्टाचार की शिकायतों की निष्पक्ष जाँच हो और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से उनके कार्यों का हिसाब माँगा जा सके। यदि किसी विभाग में लापरवाही सामने आती है, तो केवल छोटे कार्रचारियों पर कार्रवाई करके पूरे प्रकरण को समाप्त मान लेना पर्याप्त नहीं होगा। जहाँ जिस स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित होती है, वहाँ उसी के अनुरूप निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। इससे न केवल पीड़ित को न्याय मिलने की संभावना बढ़ती है, बल्कि भविष्य में लापरवाही रोकने का संदेश भी जाता है। कानून का भय और न्याय का विश्वास, दोनों जरूरी:

एक मजबूत व्यवस्था के लिए केवल दंड का भय पर्याप्त नहीं है। नागरिकों को यह विश्वास भी होना चाहिए कि उनके साथ अन्याय होने पर उन्हें न्याय मिलेगा। कानून का निष्पक्ष पालन, पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही तथा न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता इसी विश्वास को मजबूत करते हैं। अपराधी कितना प्रभावशाली है, पीड़ित कितना गरीब है या शिकायत करने वाला व्यक्ति सामाजिक रूप से कितना कमजोर है—इन आधारों पर न्याय की दिशा नहीं बदलनी चाहिए। कानून के सामने समानता लोकतंत्र की मूल भावना है। यदि आम नागरिक को लगे कि प्रभावशाली व्यक्ति के लिए रास्ते अलग हैं और कमजोर व्यक्ति के लिए नियम अलग, तो यह धारणा संस्थाओं के प्रति विश्वास को चोट पहुँचाती है। यह भी आवश्यक है कि अप्रवाह, अधूरी जानकारी और शोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट दावों के आधार पर किसी को दोषी घोषित न किया जाए। निष्पक्ष जाँच और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए ही सच्चाई सामने लाई जा सकती है। न्याय की माँग जितनी आवश्यक है, न्यायपूर्ण प्रक्रिया भी उतनी ही आवश्यक है। समाज भी अपनी जिम्मेदारी से मुँह न मोड़े: सारी जिम्मेदारी शासन पर डालकर समाज स्वयं को निंदेप नहीं ठहरा सकता। परिवारों में बढ़ती कटुता, पड़ोसियों के प्रति उदासीनता, सार्वजनिक स्थानों पर गतत आचरण देखकर भी चुप रहना और अन्याय के समय पीड़ित का साथ न देना भी सामाजिक कमजोरी के संकेत हैं। जब किसी कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय हो, तो समाज को कानूनसम्मत तरीके से उसकी सहायता करनी चाहिए। जब किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हो, तो तमामशयान बनने के बजाय सुरक्षित और उचित सहायता उपलब्ध कराने का तामाश होनी चाहिए। जब किसी बुजुर्ग को सहारे की जरूरत हो, तो उसे बोझ समझने के बजाय सम्मान देना चाहिए। और जब किसी सार्वजनिक समस्या का समाधान सामूहिक प्रयास से संभव हो, तो नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। समाज की संवेदनशीलता ही व्यवस्था को जागरूक करने की शक्ति बन सकती है। जागरूक नागरिक प्रश्न पूछते हैं, तथ्यों की पड़ताल करते हैं, शिकायतों को उचित मंच तक पहुँचाते हैं और जगहित के मुद्दों को जीवंत रखते हैं। यह विरोध के लिए विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अगर जरूरत है ठोस कदमों को: समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए शासन और प्रशासन को कुछ बुनियादी प्राथमिकताओं पर निरंतर काम करना होगा। गंभीर अपराधों की बुनियादों पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित हो। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा को व्यावहारिक प्राथमिकता मिले। सरकारी योजनाओं के लाभ और खर्च का पारदर्शी मूल्यांकन हो। महँगाई के दबाव से प्रभावित परिवारों और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए प्रभावी अवसर बढ़ाए जाएँ। प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामलों में जिम्मेदारी तब हो तथा कार्रवाई की जानकारी जनता तक पहुँचे।

उपचुनावों में करारी शिकस्त के बाद अब किस पर ठीकरा फोड़ेगी कांग्रेस?



अशोक भाटिया

भारतीय लोकतंत्र का मिजाज अब पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का चुनावी शिकस्त के बाद का बर्ताव आज भी पुराना और पूरी तरह अनुमानित नजर आता है। हाल ही में अक्टूबर 2026 में संपन्न हुए लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के नतीजों ने एक बार फिर कांग्रेस की सांगठनिक कमजोरियों और वैचारिक खोखलेपन को पूरी तरह उजागर कर दिया है। असम की प्रतिष्ठित नगांव लोकसभा सीट से लेकर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और मुस्लिम-बहुल रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र, तथा पुदुचेरी की थंडूचंवडी सीट तक—हर तरफ कांग्रेस को करारी और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है। इस ताजा चुनावी झटके ने राजनीतिक गलियारों में एक गंभीर और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि लगातार मिल रही इन पराजयों के बाद अब कांग्रेस अपनी नाकामी का ठीकरा किस संवैधानिक संस्था, व्यक्ति या व्यवस्था के सिर पर फोड़ेगी? कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व का यह इतिहास रहा है कि

जब भी चुनावी नतीजे उनके विपरीत आते हैं, वे बिना किसी पुख्ता सबूत के देश की सबसे विश्वसनीय संवैधानिक संस्थाओं पर कीचड़ छछाना शुरू कर देते हैं। इन उपचुनावों के मतदान से एेन पहले, दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया उग्र प्रदर्शन इसी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था। कांग्रेस ने संश्लाल ईंटेंसिवरिवीजन की आड़ में 'करोड़ों मतदाताओं के नाम कोटे जाने' और 'वोट चोरी' का एक भ्रामक नैरेटिव गढ़ने की पुरजोर कोशिश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट के वैधानिक स्पष्टीकरणों और स्वतंत्र जांचों ने पूरी तरह खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का इस पर बेहद कड़ा और तार्किक पक्ष है कि जब कांग्रेस हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या तेलंगाना में चुनाव जीती है, तब लोकतांत्रिक प्रक्रिया और निर्वाचन प्रणाली बिल्कुल पवित्र हो जाती है, लेकिन असम के नगांव या बंगाल के रेजीनगर में जनता जब उन्हें नकार देती है, तो वही व्यवस्था 'कठपुतली' नजर आने लगती है। यह दोहरा रवैया न केवल देश के करोड़ों मतदाताओं के विवेक का अपमान है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय लोकतंत्र की छवि को धूमिल करने का एक गैर-जिम्मेदाराना प्रयास भी है।

पश्चिम बंगाल की रेजीनगर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे कांग्रेस के पारंपरिक तुष्टिकरण के नैरेटिव पर सबसे बड़ा और सीधा प्रहार हैं। लगभग 70 प्रतिशत

मुस्लिम आबादी वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार शंखराव सरकार ने करीब 75,000 से अधिक वोटों के विशाल अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस सीट पर कांग्रेस दूर-दूर तक मुकाबले में भी नजर नहीं आई। कांग्रेस हमेशा से यह मानकर चलती रही है कि देश का अल्पसंख्यक मतदाता उसका बंधुआ वोट बैंक है, जिसे केवल बहुसंख्यक राष्ट्रवाद का डर दिखाकर हर बार हासिल किया जा सकता है। लेकिन रेजीनगर की समझदार जनता ने यह साबित कर दिया है कि अब देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, केवल 'मुप्त



के खोखले वादों' या 'डराने की राजनीति' के बहकावे में आने वाला नहीं है। जनता अब सड़कों के निर्माण, आधुनिक अस्पतालों, बेहतर शिक्षा और औद्योगिक पार्कों जैसे बुनियादी विकास को प्राथमिकता दे रही है। कांग्रेस अपनी इस वैचारिक और रणनीतिक हार को स्वीकार करने के बजाय, इस जनदेश को भी रद्दवीकरण का दुष्परिणामर बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, जो वह दशार्ता है कि पार्टी अभी भी जमीनी हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

जब चुनाव आयोग और ईवीएम पर उठाए गए सवाल जनता के बीच बेअसर साबित होने लगते हैं, तो

कांग्रेस अपने तरकश से 'केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग' का पुराना तीर निकाल लेती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का यह लगातार आरोप रहता है कि भाजपा सरकार केेंद्रीय अन्वेषक ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय का भय दिखाकर विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करती है और स्वतंत्र रूप से प्रजाप नहीं करने देती। लेकिन सच यह है कि ये तमाम जांच एजेंसियां माननीय अदालतों और न्यायपालिका के कड़े निदेशों तथा प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर ही कानूनी कार्रवाई करती हैं। चुनाव में पराजय मिलने पर इसे जनता का साफ फैसला मानने के बजाय रस्ताकूद दल द्वारा लोकतंत्र के दमनर का परिणाम घोषित कर देना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। भाजपा और राजनीतिक विक्षेकों का स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस लगातार विक्रिप्त कार्ड खेलकर अपनी आंतरिक कमजोरियों, नेतृत्वहीनता और दिशाहीन नीति को छिपाने का प्रयास करती है, लेकिन देश की जागरूक जनता अब इस राजनीतिक ड्रामे के पीछे की असलियत को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है।

इन उपचुनावों के नतीजों ने न केवल कांग्रेस की सांगठनिक अक्षमता को उजागर किया है, बल्कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के भीतर की गहरी दरारों को भी संरेआम कर दिया है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कडगम द्वारा कांग्रेस की रणनीतियों पर संरेआम सवाल उठाना और राहुल गांधी के आंदोलन से खुद को दूर रखना यह साफ करता है कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस के

बोझ को ढोने के मूड में नहीं हैं। पुदुचेरी की थंडूचंवडी सीट पर कांग्रेस की करारी हार ने यह साबित कर दिया है कि दक्षिण भारत में भी उसकी पकड़ लगातार ढीली हो रही है। क्षेत्रीय दलों को अब यह भली-भाति समझ आ गया है कि कांग्रेस के पास न तो कोई स्पष्ट राष्ट्रीय विजन है और ना ही भाजपा के मजबूत विकासवादी नैरेटिव का कोई व्यावहारिक तोड़। शीर्ष स्तर पर खुद को विपक्ष का इकलौता चेहरा साबित करने की राहुल गांधी की होड़ ने गठबंधन के अन्य मजबूत सहयोगियों के भीतर एक गंभीर असुरक्षा और असंतोष की भावना पैदा कर दी है, जिसका सीधा चुनावी नुकसान जमीन पर देखने को मिल रहा है। जब बाहरी बहानों की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, तो कांग्रेस का आंतरिक तंत्र एक विशेष रक्षाल्पक मुद्रा अपना लेता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य 'गांधी परिवार' के शीर्ष नेतृत्व को किसी भी प्रकार की जवाबदेही से सुरक्षित बचाना होता है। इन उपचुनावों में भी, असम के नगांव में सिबामनी बोराली करारी हार और बंगाल के नंदीग्राम में मिली शिकस्त के बाद, प्रदेश स्तर के नेताओं की आपसी गुटबाजी, स्थानीय स्तर पर कमजोर प्रबंधन और भीतरघात को मुख्य कारण ठहराया जाने लगा है। प्रादेशिक अस्थैश्यों और स्थानीय प्रभारियों पर हार का सारा ठीकरा फोड़कर शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह पाक-साफ घोषित कर दिया जाता है। इस समंती और दरबारी संस्कृति के कारण पार्टी के भीतर कड़क भी ईमानदारों पारदर्शी आत्ममंथन नहीं हो पाता।

जब तक पार्टी हार के वास्तविक कारणों—जैसे कार्यकताओं की उपेक्षा, राष्ट्रीय विजन का अभाव और जमीनी मुद्दों से दूरी—पर खुलकर चर्चा नहीं करेगी, तब तक सुधारात्मक कदम उठा पाना पूरी तरह असंभव है।

अक्टूबर 2026 के ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए महज एक चुनावी हार नहीं हैं, बल्कि एक गंभीर और निर्णायक चेतावनी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एकलौट का 'विकसित भारत' का संकल्प, बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूत नीतियां देश के मतदाताओं के दिलों में गहरा विश्वास पैदा कर चुकी हैं। जनता अब खोखली बयानबाजी, संसद से सड़क तक के ड्रामे और संवैधानिक संस्थाओं पर किए जाने वाले निराधार हमलों से पूरी तरह ऊब चुकी है। कांग्रेस को अब यह समझना ही होगा कि चुनाव सोशल मीडिया के नैरेटिव या विदेशी दलों पर दिए गए बयानों से नहीं, बल्कि देश के आम नागरिकों के, सुख-दुख में उनके साथ खड़े होने और जमीनी स्तर पर कड़ा संघर्ष करने से जीते जाते हैं। अगर कांग्रेस अब भी अपनी हरी वैधानिक हार का ठीकरा चुनाव आयोग, ईवीएम, केेंद्रीय एजेंसियों या परिस्थितियों पर फोड़ती रही, तो वह दिन दूर नहीं जब भारतीय राजनीति के मुख्य पटल से उसका अस्तित्व पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएगा। समय की मांग है कि कांग्रेस बहानों की राजनीति को छोड़कर एक जिम्मेदार और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना सीखे।

वन्यजीवों की घटती आबादी

‘पृथ्वी पर जीवन की विविधता मानव सभ्यता के अस्तित्व का आधार है। वन, नदियाँ, महासागर, घास के मैदान और आर्द्रभूमियाँ न केवल वन्यजीवों को आश्रय प्रदान करती हैं, बल्कि भोजन, स्वच्छ जल, जलवायु संतुलन तथा आजीविका के लिए भी आवश्यक हैं। किंतु तीव्र आर्थिक विकास, प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन और पर्यावरणीय असंतुलन ने जैव विविधता पर गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वन्यजीव आबादी में गिरावट के माध्यम से इसी संकट को उजागर करती है। यह केवल कुछ प्रजातियों के कम होने की कहानी नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच बिगड़ते संबंधों का प्रतिबिंब है।

रिपोर्ट में दर्ज वन्यजीव आबादी में गिरावट का अर्थ पृथ्वी पर मौजूद सभी पशुओं की कुल संख्या में समान अनुपात में कमी आना नहीं है। यह मुख्यतः निगरानी की गई स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर और मछली प्रजातियों की आबादी में समय के साथ हुए औसत परिवर्तन को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में बाघों, पक्षियों और मछलियों की आबादी लगातार घट रही है, तो यह उनके प्राकृतिक आवास, भोजन की उपलब्धता और प्रजनन परिस्थितियों में प्रतिकूल बदलाव का संकेत हो सकता है। इसी प्रकार, मीठे पानी के परिस्थितिकी तंत्र में आबादी की तीव्र गिरावट नदियों, झीलों और आर्द्रभूमियों पर बढ़ते दबाव को दर्शाती है। हालाँकि,

महँगाई की आग और रेपो रेट का ब्रेक

महँगाई किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए केवल बढ़ती कीमतों का सवाल नहीं है, बल्कि यह आम नागरिक की क्रयशक्ति, बचत, निवेश और जीवन-स्तर को सीधे प्रभावित करती है। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो समान आय में परिवार पहले की तुलना में कम वस्तुएँ खरीद पाते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की होती है। इसी उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर रेपो रेट में बदलाव करता है।

रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उपलब्ध कराता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंकों के लिए केेंद्रीय बैंक से धन लेना महंगा हो जाता है। इसका असर धीरे-धीरे बैंक ऋण की ब्याज दरों पर पड़ता है, और घरों तथा व्यवसायों के लिए कर्ज लेना महँगा हो सकता है। यही प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में मांग को नियंत्रित करे और मांग-जनित महँगाई को कम करने में मदद करती है।

रेपो रेट बढ़ने का सबसे सीधा

आबादी में गिरावट और प्रजातियों के विलुप्त होने के बीच अंतर है। कुछ प्रजातियों की संख्या घटने का अर्थ यह नहीं कि वे विलुप्त हो चुकी हैं। इसलिए वन्यजीवों की घटती आबादी को प्रकृति के स्वास्थ्य का चेतावनी संकेतक समझना चाहिए, न कि सभी जीवों के कुल विनाश का प्रत्यक्ष माप।

जैव विविधता के ह्रास का सबसे प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासों का विनाश और विखंडन है। वनों की कटाई, कृषि भूमि का विस्तार, खनन, शहरीकरण, सड़क निर्माण तथा औद्योगिक परियोजनाएँ वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों को सीमित कर देती हैं। जब जंगल छोटे-छोटे हिस्सों में बँट जाते हैं, तो जानवरों की आवाजाही, प्रजनन और भोजन प्राप्त करने की क्षमता प्रभावित होती है। भारत में वन क्षेत्रों के निकट मानव बस्तियों और आधारभूत संरचनाओं का विस्तार हाथियों तथा तेंदुओं के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष को बढ़ा सकता है। प्राकृतिक आवासों का विनाश केवल जीवों को आश्रय से वंचित नहीं करता, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य शृंखला और प्राकृतिक संतुलन को कमजोर करता है।

प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन भी जैव विविधता के लिए गंभीर चुनौती है। अत्यधिक शिकार, अवैध वन्यजीव व्यापार, अनियंत्रित मछली पकड़ना तथा लकड़ी का अत्यधिक दोहन अनेक प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। जब किसी प्रजाति से उसकी प्राकृतिक



-प्रियंका सौरभ

पुनरुत्पादन क्षमता से अधिक संसाधन प्राप्त किए जाते हैं, तो उसकी आबादी में गिरावट आने लगती है। भारत में बाघों के अंगों, पैंगोलिन के शक्कों और अन्य वन्यजीव उत्पादों का अवैध व्यापार इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। इसी प्रकार, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक मत्स्य दोहन खाद्य शृंखला को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, वन्यजीव उत्पादों की बढ़ती माँग और अवैध व्यापार के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क संरक्षण संबंधी प्रयासों को कमजोर करते हैं।

जलवायु परिवर्तन जैव विविधता के संकट की और गहरा कर रहा है। वैश्विक तापवृद्धि, वर्षा चक्र में परिवर्तन, सूखा, बाढ़, समुद्र-स्तर में वृद्धि तथा महासागरों का अम्लीकरण वन्यजीवों के अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। तापमान में बदलाव से प्रजातियों के प्रजनन क्षमता, प्रवास और भोजन की उपलब्धता में परिवर्तन हो सकता है। समुद्री तापमान बढ़ने से प्रवाल विरजन की घटनाएँ बढ़ती हैं, जिससे प्रवाल भित्तियों पर निर्भर

बढ़ जाती है। कई कंपनियाँ ऐसे निवेश को कुछ समय के लिए टाल सकती हैं, जिनसे अपेक्षित लाभ ब्याज लागत की तुलना में कम हो। इससे अत्यधिक आर्थिक गतिविधि पर कुछ नियंत्रण आता है और अर्थव्यवस्था में मांग का दबाव कम हो सकता है।

रेपो रेट का एक महत्वपूर्ण प्रभाव बैंकिंग प्रणाली में ऋण वृद्धि पर भी पड़ता है। महँगे ऋण के कारण बैंक ऋण की मांग घट सकती है। यदि अर्थव्यवस्था में कर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा हो और उसके कारण उपभोग तथा निवेश असामान्य रूप से बढ़ रहे हों, तो मौद्रिक सख्ती उस गति को संतुलित करने का काम करती है। महँगाई केवल वर्तमान कीमतों का विषय नहीं है; भविष्य में कीमतें कितनी बढ़ेंगी, इसकी लोगों की धारणा भी महत्वपूर्ण होती है। जब आरबीआई महँगाई के दबाव के बीच रेपो रेट बढ़ाता है, तो वह बाजार को यह संकेत देता है कि केेंद्रीय बैंक मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है। इससे महँगाई की अपेक्षाओं को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। यदि व्यवसायों और उपभोक्ताओं को विश्वास हो कि केेंद्रीय बैंक कीमतों को अनियंत्रित नहीं होने देगा, तो वे भविष्य की कीमतों और मजदूरी को लेकर अत्यधिक मुद्रास्फीतिकारी निर्णय लेने से बच

अनेक जीव प्रभावित होते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में बदलती जलवायु पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र और वहाँ रहने वाली प्रजातियों के लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न करती है। इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन पहले से ही कमजोर पारिस्थितिकी तंत्रों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। प्रदूषण भी जैव विविधता के ह्रास का एक प्रमुख कारक है। औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, प्लास्टिक तथा सीबेंज मिट्टी और जल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। कृषि क्षेत्रों से बहकर आने वाले रसायन जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी पैदा कर सकते हैं, जिससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए जीवित रहना कठिन हो जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री कछुओं, पक्षियों और मछलियों के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। इसके अतिरिक्त, प्रकाश और ध्वनि प्रदूषण वन्यजीवों के व्यवहार, संचार तथा प्रजनन प्रक्रियाओं को बाधित कर सकते हैं। आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ भी स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुँचाती हैं। भारत में लैंडाना जैसी आक्रामक वनस्पति कुछ वन क्षेत्रों में स्थानीय वनस्पतियों के पुनर्जनन को प्रभावित करती है और प्राकृतिक आवासों की संरचना में बदलाव लाती है। जैव विविधता संरक्षण के लिए सर्वप्रथम प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्रों के पुनर्स्थापन को प्राथमिकता देनी चाहिए। वनों, आर्द्रभूमियों, घास के

सकते हैं। रेपो रेट में बढ़ोतरी का एक अन्य संभावित प्रभाव रुपये की विनिमय दर पर पड़ सकता है। अपेक्षाकृत ऊँची घरेलू ब्याज दरें वित्तीय बरिसंपत्तियों को अधिक आकर्षक बना सकती हैं और पूँजी प्रवाह को समर्थन मिल सकता है। इससे रुपये पर अत्यधिक अवमूल्यन का दबाव कम हो सकता है। भारत कच्चे तेल सहित कई महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात करता है। रुपये की कमजोरी से आयात महँगा होता है और इससे आयातित महँगाई बढ़ सकती है। इसलिए विनिमय दर में स्थिरता भी महँगाई नियंत्रण में अप्रत्यक्ष भूमिका निभा सकती है।

हालाँकि रेपो रेट बढ़ाना कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसका अर्थव्यवस्था पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़े। इसका सबसे बड़ा जोखिम आर्थिक विकास की गति पर पड़ सकता है। ऊँची ब्याज दरों से परिवारों का खर्च घट सकता है और कंपनियों का निवेश धीमा हो सकता है। इसका प्रभाव आवास, ऑटोमोबाइल, निर्माण और अन्य ब्याज-संवेदनशील क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत अधिक पड़ सकता है। छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए यह चुनौती और गंभीर हो सकती है, क्योंकि वे अक्सर बैंक ऋण पर अधिक निर्भर होते हैं।

मैदानों, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों का संरक्षण आवश्यक है। संरक्षित क्षेत्रों के साथ वन्यजीव गलियारों का विकास किया जाना चाहिए, ताकि जानवर अलग-थलग आबादियों के बीच आवागमन कर सकें। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ने बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण को महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान किया है। इसी प्रकार, क्षतिग्रस्त वनों का स्थानीय प्रजातियों के माध्यम से पुनर्स्थापन तथा नदियों और आर्द्रभूमियों का पुनर्जीवन जैव विविधता की रक्षा में सहायक हो सकता है।

संरक्षण के प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए वैज्ञानिक निगरानी और अनुसंधान भी आवश्यक हैं। केमरा ट्रैप, उपग्रह आधारित निगरानी, डीएनए विश्लेषण तथा प्रजातियों की स्थिति का बेहतर आकलन किया जा सकता है। निगरानी में उन प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों को भी शामिल करना चाहिए जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। साथ ही, स्थानीय और आदिवासी समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। संयुक्त वन प्रबंधन, संरक्षण आधारित आजीविका, पर्यावरण पर्यटन तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान करना संरक्षण के प्रति विश्वास बढ़ा सकता है। कृषि, उद्योग और मत्स्य पालन में सतत पद्धतियों को अपनाना, प्लास्टिक कचरे को कम करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का

दूसरी ओर, बचतकताओं को बढ़ी हुई ब्याज दरों से कुछ लाभ मिल सकता है। बैंकों द्वारा जमा पर अधिक ब्याज दिए जाने की स्थिति में सावधि जमा और अन्य बचत साधनों का आकर्षण बढ़ सकता है। इससे उपभोग की बजाय बचत को प्रोत्साहन मिलता है, जो अत्यधिक मांग को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है।

लेकिन भारत में महँगाई का बड़ा हिस्सा हमेशा मांग से पैदा नहीं होता। खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, खराब मानसून, आपूर्ति बाधाएँ, वैश्विक जंस कीमतों में उछाल, कच्चे तेल की कीमत और भू-राजनीतिक संकट जैसी परिस्थितियाँ आपूर्ति-पक्ष को महँगाई पैदा कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में केवल रेपो रेट बढ़ाने से समस्या का मूल समाधान नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि व्याज या टमाटर की कीमत आपूर्ति कम होने के कारण बढ़ रही है, तो ब्याज दर बढ़ाने से इनकी आपूर्ति तत्काल नहीं बढ़ेगी।

इसलिए भारत में महँगाई नियंत्रण की रणनीति बहुआयामी होनी चाहिए। आरबीआई को बदलते संकेतकों के आधार पर रेपो रेट में सावधानीपूर्वक बदलाव करना चाहिए। सरकार को खाद्य भंडारण, कृषि आपूर्ति शृंखला, परिवहन, आयात-निर्यात प्रबंधन

विवेकपूर्ण उपयोग करना भी आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, वन्यजीव संरक्षण से संबंधित कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, अवैध व्यापार पर नियंत्रण और विकास परियोजनाओं का निष्पक्ष पर्यावरणीय आकलन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा देशों को जैव विविधता के संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्रों के पुनर्स्थापन और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए साझा दिशा प्रदान करती है। इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण, तकनीकी सहयोग और जवाबदेही आवश्यक हैं।

अंततः, वन्यजीव आबादी में गिरावट प्रकृति के साथ बढ़ते असंतुलन का गंभीर संकेत है। इसका प्रभाव केवल वन्यजीवों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि खाद्य सुरक्षा, जल उपलब्धता, जलवायु स्थिरता और मानव कल्याण को भी प्रभावित करता है। इसलिए संरक्षण को विकास के विरोध के रूप में नहीं, बल्कि सतत विकास की अनिवार्य शर्त के रूप में देखा जाना चाहिए। वैज्ञानिक प्रमाण, प्रभावी नीतियाँ, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जिम्मेदार उपभोग को एक साथ आगे बढ़ाकर ही जैव विविधता के ह्रास को रोक जा सकता है। प्रकृति की रक्षा केवल भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व नहीं, बल्कि वर्तमान मानव समाज के अस्तित्व और समृद्धि की भी आवश्यकता है।

और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुधारने पर

साई परिवार सेवाभावी ट्रस्ट की ओर से आश्रम विद्यालय में पितृपक्ष अन्नदान कार्यक्रम संपन्न



पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। साई परिवार सेवाभावी ट्रस्ट की ओर से पितृपक्ष के अवसर पर 4 अक्टूबर 2026 को मान, विक्रमगढ़ स्थित आश्रम विद्यालय में अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछले 36 वर्षों से निरंतर संचालित इस सेवाभावी उपक्रम के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता की जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को भोजन, नाश्ता, खेल सामग्री और शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई।

इस सेवा अभियान की शुरुआत श्री मंगेश अंकुश रासम की संकल्पना से हुई थी। अनेक सहयोगियों और दानदाताओं के निरंतर सहयोग से यह उपक्रम 36 वर्षों का सफर पूरा कर सका है। ट्रस्ट की ओर से अब तक विभिन्न आश्रमशालाओं, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, मूक-बधिर विद्यालयों तथा बेघर लोगों के आश्रय केंद्रों में यथाशक्ति सहायता प्रदान की जाती रही है। इस वर्ष आयोजित कार्यक्रम में आश्रम विद्यालय के विद्यार्थियों को खेल सामग्री, खाद्य सामग्री और शैक्षणिक सामग्री प्रदान की गई। इसके साथ ही बच्चों के लिए सुबह नाश्ते में वड़ापाव तथा दोपहर में स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई। इस पहल से विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनिल वडके, संतोष बडवे, विनय सिंग, पंकज नाइक, महेश वर्मा, समीर सागवेकर, डॉ. रेवती आलवे, सदैश कनगुटकर, सौ. नंदा चौधरी, रजनी उमरसकर और सुजल राणे ने अमूल्य योगदान दिया। इस अवसर पर आश्रम विद्यालय के मुख्याध्यापक चेतन ठाकरे, तुलसीदास तांडेल, यशवंत सहित आश्रम विद्यालय के कर्मचारियों ने भी सहयोग प्रदान किया। सभी के सामूहिक प्रयासों से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ट्रस्ट के इस 36 वर्षों से जारी सेवाकार्य की अनेक लोगों ने सराहना की। साथ ही साई परिवार सेवाभावी ट्रस्ट के पदाधिकारियों, सदस्यों, सहयोगियों और हितचिंतकों को भविष्य में भी इसी तरह समाजसेवा के कार्य जारी रखने के लिए शुभकामनाएं दीं।

सेवा संकल्प अभियान के तहत वाडा में 217 से अधिक दिव्यांगजनों का यूडीआईडी पंजीयन



पालघर(उत्तरशक्ति)। पालघर जिला परिषद की ओर से संचालित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाडा तहसील में आयोजित शिविर में 217 से अधिक दिव्यांगजनों का वऊन्नक (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) पंजीयन किया गया। इस पहल से दिव्यांगजनों की सरकारी योजनाओं और विभिन्न शासकीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। शिविर के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी धर्मों, स्वस्थकर्मियों, संबंधित कर्मचारियों और दिव्यांग संगठनों के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस अभियान के माध्यम से दिव्यांगजनों की आवश्यक प्रमाणपत्र एवं पहचान संबंधी प्रक्रिया पूरी करने का अवसर मिला। इस अवसर पर प्रह्लाद दिव्यांग क्रांति संस्था, पालघर के जिलाध्यक्ष एवं ओम साई दत्त विकलांग सेवा संस्था के संस्थापक-अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने शिविर के आयोजन में सहयोग देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। इस दौरान प्रह्लाद दिव्यांग क्रांति संस्था, पालघर के जिलाध्यक्ष एवं ओम साई दत्त विकलांग सेवा संस्था के संस्थापक-अध्यक्ष सुनील गुप्ता, पालघर तहसील अध्यक्ष सुनील चुरी, डहाणू तहसील कार्याध्यक्ष सचिन तांडेल, वाडा तहसील अध्यक्ष सुनील निपुते, वाडा तहसील सचिव हरेश्वर पाटील, तहसील कार्याध्यक्ष विनोद पावडे, ओम साई दत्त विकलांग सेवा संस्था के वाडा तालुका उपाध्यक्ष अविनाश जाधव एवं वैभव पाटील, तहसील सचिव सचिन मोरे तथा सहयोगी सुजाता ठाकरे सहित तहसील समिति के सभी पदाधिकारी व सहस्रगण उपस्थित रहे। दिव्यांगजनों के पंजीयन की इस पहल को सफल बनाने में सभी संबंधितों के योगदान की सराहना की गई। साथ ही दिव्यांगजनों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर सहयोग करने का संकल्प व्यक्त किया गया।

मीरा रोड में देह व्यापार के लिए महिला को भेजने का आरोप, एक महिला गिरफ्तार

मीरा-भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा रोड के सिल्वर पार्क स्थित एक लॉजिंग एंड बोर्डिंग में कथित देह व्यापार के मामले में मीरा-भायंदर पुलिस के महिला अत्याचार निवारण एवं विशेष बाल संरक्षण व देखभाल प्रकोष्ठ ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, हिंदी धारावाहिकों, फोटोशूट और वेब सीरीज में काम करने वाली एक महिला को कथित रूप से अनैतिक गतिविधियों के लिए भेजे जाने की सूचना मिली थी। कार्रवाई के दौरान पीड़ित महिला को मुक्त कराकर सुरक्षा के लिए मुंबई के कांदिवली स्थित रेस्क्यू फाउंडेशन में रखा गया है। एनजीओ से मिली थी सूचना पुलिस को 8 अक्टूबर 2026 को गैर-सरकारी संगठन हाएक्सोडस रोड इंडिया फाउंडेशनह्व के माध्यम से सूचना मिली थी कि रमेश कुमार नामक व्यक्ति और सोनिया नाम से पहचानी जाने वाली एक महिला कथित रूप से लड़कियों को देह व्यापार के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। शिकायत के अनुसार, आरोपियों द्वारा व्हाट्सऐप के माध्यम से पुरुष ग्राहकों को महिलाओं की तस्वीरें भेजकर पैसे के बदले अनैतिक गतिविधियों के लिए संपर्क किया जा रहा था। पुलिस ने बिछाया जाल सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर एक फर्जी ग्राहक और दो पंच गवाहों की सहायता से कार्रवाई की योजना बनाई।

उत्तरशक्ति

* संपादक: ओमप्रकाश प्रजापति

* उप संपादक: प्रेम चंद मिश्रा

*प्रबंध संपादक: डा. शेषधर बिन्द

उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।

पत्राचार कार्यालय :

उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)

मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमाणसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जबल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37

मो.- 9554493941

email ID- uttarshaktinews@gmail.com

ठाणे जिले में स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के विकास के लिए 400 करोड़ का प्लान

कल्याण (उत्तरशक्ति)। ठाणे जिले में शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और नागरिक सुविधाओं का स्तर बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने 400 करोड़ रुपये का व्यापक विकास आराखड़ा तैयार किया है। इसके तहत जिला परिषद, महानगरपालिका और नगरपालिका क्षेत्रों के स्कूलों के आधुनिकीकरण एवं शैक्षणिक सुविधाओं के विकास के लिए करीब 300 करोड़ रुपये, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये का नियोजन किया गया है। इसके अलावा शहरों के सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा दलित बस्तियों और झोपडपट्टी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी विशेष जोर दिया

जाएगा। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा समिति) की ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में इन योजनाओं के नियोजन, निधि की उपलब्धता और कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता दिशा समिति के अध्यक्ष एवं सांसद डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने की।

स्कूलों को बनाया जाएगा आधुनिक और स्मार्ट: जिले के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा, इंटरनेट कनेक्टिविटी, आधुनिक कक्षाएं, स्वच्छ पेयजल, लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय और बेहतर रसोईघर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। सक्षम स्कूल अभियान के तहत आवश्यकता के अनुसार स्कूलों का पुनर्निर्माण कर उन्हें स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।

भिंवंडी में पॉलिश कंपनी में जोरदार धमाका, चार मजदूर झुलसे; दो की हालत गंभीर

भिंवंडी। भिवंडी तालुका के सोनाले गांव स्थित लक्ष्मी कपाउंड में शनिवार, 10 अक्टूबर की सुबह करतूर पॉलिश कंपनी में अचानक हुए विस्फोट के बाद आग लग गई। इस हादसे में चार मजदूर झुलसकर घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान शहाजहान शेख, वियय कुमार वर्मा, नंदकिशोर यादव और नितिन कुमार के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कंपनी में पॉलिश करने वाली मशीन में अचानक विस्फोट होने से आग भड़क उठी। घटना के बाद कंपनी में अफरा-तफरी मच गई और वहां काम कर रहे मजदूरों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही भिवंडी अग्निरामान दल की दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।



दमकल कर्मियों ने करीब दो घंटे तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद राहत कार्य पूरा किया गया। हादसे की जानकारी मिलने पर भिवंडी तालुका पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस विस्फोट के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है। साथ ही, कंपनी में सुरक्षा व्यवस्था और दुर्घटना से जुड़ी अन्य परिस्थितियों को भी जांच की जा रही है।

समाजवादी पार्टी मुलुंड द्वारा मनाई गयी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि

मुंबई। समाजवादी पार्टी की मुलुंड विधानसभा इकाई की ओर से पार्टी के संस्थापक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने नेताजी के चित्र पर श्रद्धासुप्तन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों एवं समाजवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का आयोजन मुलुंड विधानसभा अध्यक्ष जीवन लाल यादव के नेतृत्व में नागरिक सभा हॉल, जवाहरलाल नेहरू रोड, मुलुंड पश्चिम में मुलुंड रेलवे स्टेशन के बगल में किया गया।



कार्यक्रम में ईशान मुंबई जिला अध्यक्ष शशिकांत यादव, जिला प्रमुख महासचिव दीनानाथ यादव, जिला उपाध्यक्ष रवींद्रनाथ यादव, राम कैलाश सरोज, विनोद शर्मा, सुशील यादव, सभाजीत यादव, अखिलेश यादव, वीरेंद्र यादव, शशि, विजय यादव, धीरेंद्र यादव, डॉ. जे.एस. यादव सिंह तथा प्रभाकर यादव सहित पार्टी के अनेक

प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष में एसएम खान द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन

मुंबई। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री के पद पर 25 वर्ष पूर्ण करने तथा जन्मदिन के उपलक्ष में पूरे महाराष्ट्र में एक महीना तक चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष एसएम खान ने जोगेश्वरी वसोवा विधानसभा के आनंद नगर स्थित अपने कार्यालय के पास मेडिकल शिविर का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय नागरिकों के लिए मेडिकल चेकअप, चश्मा विवरण तथा मुफ्त दवाइयों का विवरण किया गया।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आशुभानुसार एक महीने का कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में सेवा पखवाड़ा के रूप में चलाया



जा रहा है।

एसएम खान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों से देश की आम आवांम पूरी तरह से संतुष्ट है। देश और प्रदेश आज विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है।

दिशा समिति के अध्यक्ष एवं सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने जिला प्रशासन को दिए निर्देश

स्कूल परिसरों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं, वर्षा जल संचयन, विद्यार्थियों के लिए बेहतर विश्राम कक्ष तथा शैक्षणिक एवं प्रेरणादायी चित्रों से सजी दीवारें विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए अदार रसोईघर बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए अनुभवी शिक्षकों के साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा। प्रत्येक स्कूल की अद्यतन जानकारी रखने, हर वर्ष उसका मूल्यांकन करने और जरूरत के अनुसार सुधार करने की व्यवस्था विकसित की



जाएगी। जिला परिषद, महानगरपालिकाओं और नगरपालिकाओं के माध्यम से आवश्यक निधि जुटाकर आधुनिकीकरण के कार्य नियोजित तरीके से पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।

शहरों के सौंदर्यीकरण और नागरिक सुविधाओं पर जोर: शहरों में प्रमुख सड़कों का सौंदर्यीकरण, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था, तालाबों और उद्यानों का विकास तथा सार्वजनिक स्थानों को बेहतर बनाने की योजना है।

निर्माण स्थल पर 58 वर्षीय मजदूर की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

मजदूरों का आरोप—कंपनी नहीं देती सुरक्षा उपकरण, हादसे के बाद मदद के लिए भी भटकना पड़ता है

कल्याण। कल्याण पूर्व के आडिवली-ढोकली क्षेत्र में स्थित माउंटेन ड्रीम सिटी निर्माण स्थल पर एक 58 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान रामजीबाबू कन्हैयालाल यादव के रूप में हुई है। इस घटना के बाद निर्माण स्थल पर मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज आकस्मिक मृत्यु की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 9 अक्टूबर को रात करीब 10:37 बजे सामने आई। हादसा आडिवली-ढोकली, कल्याण पूर्व स्थित माउंटेन ड्रीम सिटी कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ। घटना के बाद मानपाड़ा पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए डॉंबिवली के शास्त्रीनगर अस्पताल भेजा गया।



सुरक्षा उपकरण नहीं मिलने का मजदूरों का आरोप: नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कुछ मजदूरों ने आरोप लगाया कि निर्माण कंपनी की ओर से मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। उनका कहना है कि निर्माण

स्थल पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता बरती जानी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि किसी दुर्घटना के बाद प्रभावित मजदूरों और उनके परिवारों की मदद

के लिए कोई संगठन आगे नहीं आता। इस घटना के बाद से संबंधित लोग पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने को मजबूर हैं। मजदूरों का आरोप है कि गरीब मजदूरों की शिकायतों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि ऐसे मामलों में विकासकों को राहत मिलती है। **मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा ?:** इस घटना ने निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा, उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने और दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवार को सहायता मिलने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने ला दिया है। अब पवाल यह है कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने और मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए संबंधित विभाग कब ठोस कदम उठाएंगे।

ओबीसी कृति समिति के लंबित प्रस्तावों की त्रुटियां दूर कर एनसीबीसी दिल्ली भेजेगा विभाग

मंत्रालय में सचिव आप्पासो धुलाज के साथ हुई अहम बैठक में सकारात्मक चर्चा, प्रस्तावों को जल्द आगे बढ़ाने का दिया आश्वासन

मुंबई(उत्तरशक्ति)। महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समाज की लंबित मांगों और विभिन्न जातियों को केन्द्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने से संबंधित प्रस्तावों को गति देने के लिए महाराष्ट्र ओबीसी कृति समिति ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में ओबीसी बहुजन कल्याण विभाग के सचिव आप्पासो धुलाज (आईएसएस) के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में लंबित प्रस्तावों में मौजूद तकनीकी त्रुटियों को दूर करने तथा उन्हें आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी), नई दिल्ली को शीघ्र भेजने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान सचिव आप्पासो धुलाज ने आश्वासन दिया कि विभाग स्तर पर लंबित प्रस्तावों की समीक्षा कर आवश्यक त्रुटियों को दूर करने की कार्रवाई की जायेगी। साथ ही जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से एनसीबीसी, नई दिल्ली भेजने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस आश्वासन से समिति के प्रतिनिधियों में संतोष व्यक्त किया गया। इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत 5 अक्टूबर 2026 को हुई थी। महाराष्ट्र ओबीसी कृति समिति के वरिष्ठ संरक्षक एवं पूर्व प्राचार्य पी. आर. बडगुजर तथा वरिष्ठ संरक्षक एस. एम. बडगुजर ने मंत्रालय पहुंचकर सचिव आप्पासो धुलाज से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने केन्द्रीय ओबीसी सूची में समावेशन से संबंधित लंबित प्रस्तावों की स्थिति,



प्रशासनिक देरी और इससे प्रभावित समाजों की समस्याओं की जानकारी दी। साथ ही, मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष समीक्षा बैठक आयोजित करने की मांग की। दोनों वरिष्ठ संरक्षकों के प्रयासों के बाद सचिव ने मामले पर सज्ञान लेते हुए 7 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे मंत्रालय में समीक्षा बैठक निर्धारित की। निर्धारित समय पर आयोजित बैठक में मंत्रालय के उपसचिव डॉ. वसंत माने, संबंधित कक्ष अधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। महाराष्ट्र ओबीसी कृति समिति की ओर से वरिष्ठ संरक्षक एस. एम. बडगुजर, भूषण कडेकर, विकास संसारे, आषाढ शेख, रवींद्र गोलांडे और मनमत लोकेवार सहित समिति के पदाधिकारी एवं सामाजिक प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न जातियों और समाजों को केन्द्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने से संबंधित लंबित प्रस्तावों का मुद्दा उठाया। प्रतिनिधियों ने बताया कि कुछ प्रस्ताव दस्तावेजों की कमी और तकनीकी त्रुटियों के कारण

शासन स्तर पर लंबित हैं। उन्होंने संबंधित प्रस्तावों की कमियों को दूर कर प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल की ओर से प्रस्तुत मुद्दों और दस्तावेजों पर चर्चा के बाद सचिव आप्पासो धुलाज ने सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विभाग स्तर पर आवश्यक त्रुटियों को दूर करने और संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी, ताकि प्रस्तावों को आगे की प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली को भेजा जा सके। बैठक सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। महाराष्ट्र ओबीसी कृति समिति ने उम्मीद जताई कि विभाग के इस आश्वासन से वर्षों से लंबित प्रस्तावों को गति मिलेगी और संबंधित समाजों की केन्द्रीय ओबीसी सूची में समावेशन की मांग को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब सभी की निगाहें प्रस्तावों में आवश्यक सुधार और उन्हें एनसीबीसी तक भेजने की आगामी प्रशासनिक प्रक्रिया पर टिकी हैं।

प्यासा ऑर्केस्ट्रा बार पर पुलिस का छापा, गुप्त कमरे से 10 महिलाओं समेत कुल 16 महिलाएं मुक्त

भायंदर पूर्व में महिला अत्याचार निवारण प्रकोष्ठ की कार्रवाई; मैनेजर, कैशियर समेत 12 लोग गिरफ्तार, अवैध शराब और अन्य सामग्री जब्त

कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अश्लील इशारों और नियमों के उल्लंघन की मिली थी सूचना पुलिस को 8 अक्टूबर 2026 को सूचना मिली थी कि प्यासा ऑर्केस्ट्रा बार में महिला वेट्रेस के माध्यम से कथित रूप से अश्लील इशारे करवाकर ग्राहकों को आकर्षित किया जा रहा है। साथ ही, बार में निर्धारित संख्या से अधिक महिला वेट्रेस रखने और अन्य नियमों के उल्लंघन की भी शिकायत मिली थी। सूचना की पुष्टि और आवश्यक

कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद महिला अत्याचार निवारण एवं विशेष बाल संरक्षण व देखभाल प्रकोष्ठ की टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई। रात 10:20 बजे पुलिस ने मारा छापा पुलिस टीम ने 8 अक्टूबर की रात करीब 10:20 बजे भायंदर पूर्व के नवधर रोड स्थित प्यास ऑर्केस्ट्रा बार पर छापा मारा। पुलिस के अनुसार, बार में कम रोशनी के बीच मंच पर महिलाएं प्रस्तुति दे रही थीं। आरोप है कि कुछ महिलाएं अश्लील इशारे कर ग्राहकों को



आकर्षित कर रही थीं और बार के कर्मचारी उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर एक महिला वेट्रेस और उसके साथ मौजूद एक

व्यक्ति पास के दरवाजे से भागने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने महिला वेट्रेस और उसकी साथी को भी सुरक्षित

रोक लिया। गुप्त कमरे में मिली 10 महिलाएं छापेमारी के दौरान मंच पर सात महिलाएं मौजूद थीं। इसके बाद पुलिस टीम उस दिशा में पहुंची, जहां से महिला वेट्रेस के भागने की कोशिश करने की बात सामने आई थी। वहां तलाशी लेने पर एक छिपा हुआ का कमरा मिला। कमरे का दरवाजा खोलने पर पुलिस को अंदर 10 महिलाएं मिलीं। पुलिस के मुताबिक, उस कमरे में हवा के पर्याप्त आवामान की व्यवस्था नहीं थी, जिससे वहां मौजूद महिलाओं के

जीवन और स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो सकता था। कार्रवाई के दौरान कुल 16 महिलाओं को मुक्त कराया गया। पुलिस अब बार में महिलाओं को रखने की परिस्थितियों और नियमों के उल्लंघन से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। मैनेजर और कैशियर समेत 12 लोग गिरफ्तार पुलिस ने इस मामले में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक मैनेजर, एक कैशियर, दो स्टीवर्ड, सात वेंटर और एक पुरुष संगीतकार शामिल हैं।

स्वामी: शरद फागुमन प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तनू जला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जबल, गेट क्रमांक 2, गोगोवा (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुद्रित एवं के-4, रुम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर यू समता सहकारी को.ऑ. हॉ. सौसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरगांव (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।

पत्राचार कार्यालय: मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमाणसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्ल्यू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जबल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्टाइव्सर्स की जीत में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले फरहान हक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 17 गेंदों पर 23 रन बनाए। कुलपति प्रो. आर. के. सिंह ने उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।

दूसरे मुकाबले में जफराबाद चैलेंजर्स की टीम 10 ओवर में 50 रन पर सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मडियाहू चैलेंजर्स ने तीन

लकड़ी के सामान को नुकसान पहुँचा। धुआँ प्रथम तब तक पहुँचा जब तक कि धुआँ कमियों के श्वास यंत्र पर दमककर धुआँ बाहर निकाला और आग बुझने की कार्रवाई की अभियान के दौरान कुछ दमकल कमियों की उंगलियों में आँशिक चोटें भी आई, लेकिन उन्होंने उच्चारण के बाद आपन अभियान के सखा। सुबह 8:35 बजे आग की तरह काबू पा लिया गया। लकड़ी कमियों के साहस और निपटण की स्थानीय लोगों एवं रियों ने सराहना की।